International Journal of Enhanced Research in Management & Computer Applications
ISSN: 2319-7471, Vol. 6 Issue 9, September-2017, Impact Factor: 3.578

मुरादाबाद मण्डल के औद्योगिक विकास की समस्यायें

डॉ. राकेश प्रवक्ता वाणिज्य

भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में प्रतिकुल परिस्थितियों से होकर गुजर रही है, यद्यपि विगत दशकों से भारतीय आर्थिक स्थिति को सुधारने के नियोजित प्रयास जारी है, परन्तु स्थिति में थोड़े–बहुत सुधार के उपरान्त भी निर्धनता व बेरोजगारी–समस्याओं में कमी के लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे है। वरन् कुछ क्षेत्रों में तो बड़ी तीव्रता के साथ वृद्धि जारी है। शिक्षा में वृद्धि के बावजुद शिक्षित–बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। विभिन्न पंचवर्षीय व वार्षिक योजनाओं में विकास के लक्ष्य निर्धारित किये जाते है। उनकी प्राप्ति के लिए भरस्क–प्रयत्न भी किये जाते है, परन्तु अपवादों को छोड़कर प्रायः लक्ष्य की प्राप्ति में बुरी तरह विफल हो जाते है। फलतः आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अवस्था में है। आज भी विशाल स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग नही हो पा रहा है। जन–शक्ति का विशाल भाग अकार्यशील अवस्था में है। प्रति व्यक्ति आय विश्व में निम्नतम है। पूँजी संसाधनों की आपूर्ति न्यूनतम है। उत्पादन दशायें व तकनीकी स्तर अभी भी सन्तोषजनक नहीं है। प्रति व्यक्ति उत्पादन व श्रम की उत्पादन क्षमता कम है। समाज की अनेक आवश्यकतायें अधूरी रह जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत की आर्थिक स्थिति में भारी प्रयासों के उपरान्त भी अधूरापन दिखलाई पड़ता है। अध्ययन मुरादाबाद मण्डल भी इसका अपवाद नही है। यहाँ पर भी स्वतंत्रता–प्राप्ति से पूर्व व बाद के समय में आम व्यक्ति की दशा में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। कृषक, ग्रामीण वर्ग, नगरीय क्षेत्रों के निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति में बहुत मन्द गति से सुधार हुआ है। इस प्रकार की आर्थिक दशाओं में तेजी से सुधार की आवश्यकता है। अन्यथा समाज में व्याप्त असंतोष, विघटन का कारण बन सकता है। अतः समय रहते समाज के जीवन–स्तर को ऊपर उठाया जाना चाहिए। सामाजिक जीवन में सुधार तभी आ सकता है। जबकि आर्थिक स्थिति को सुधारा जाये, उत्पादन–क्षमता में वृद्धि की जाये अतः अर्थव्यवस्था में चहुँमुखी विकास के लिए सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना प्रक्रिया को तीव्र करना होगा।

मुरादाबाद मण्डल की आर्थिक स्थिति का मुख्य आधार कृषि है क्योंकि कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अन्य वर्ग भी बहुत कुछ कृषि व कृषक –वर्ग पर आश्रित है, इतना ही नहीं नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाला व्यापारिक–वर्ग भी बहुत सीमा तक कृषि से प्रभावित होता है। इस प्रकार मुरादाबाद मण्डल की जनसंख्या का 85 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में कृषि पर आधारित है। अतः क्षेत्रीय स्तर पर कृषि ही अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है परन्तु कृषि–क्षेत्र की अपनी निश्चित सीमायें है। (क्षेत्रीय स्तर पर जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि पर निरन्तर दबाव बढ़ता जा रहा है। विगत् तीन दशकों (1980–2000) में सिंचाई क्षमता में वृद्धि, मशीनीकरण उत्तम कोटि के बीजों व रासयनिक खाद का भरपूर प्रयोग तथा नवीन कृषि विधियों को प्रयोग में लाने के कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में अभूत पूर्व वृद्धि हुई है। औद्योगिक फसलों का उत्पादन बढ़ा है, परन्तु कृषक वर्ग की आर्थिक स्थिति में संतोषजनक सुधान नहीं हुआ है। कृषकों की वार्षिक आय का औसत 3000–6000 रूपये है, जबकि भारत के अन्य क्षेत्रों में यह कही अधिक है। कृषकों के पास बहुत छोटे–छोटे आवास है, न्यूनतम वस्त्र प्रयोग करते है। पौष्टिक आहार उपलब्ध नही होता है। ऋणों के बोझ से दबे हैं। बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ है। अपने को सभ्य समाज से अलग–थलग महसूस करते हैं। हीन भावना से ग्रस्त है। अतः कृषकों को कृषि से क्या मिला? सिर्फ तन ढापने के लिए वस्त्र, शरीर को जीवित या झोपड़ी। आधुनिकता के इस युग में ऐसे समाज को क्या कहा जा सकता है? क्या उसको उचित सम्मान प्राप्त हो सकता है? क्या उसमें असंतोषजनक की भावना जन्म नहीं ले रही? बहुत से कृषकों ने तो यहाँ तक कह डाला कि इससे तो हम स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजों के राज में अच्छे थे। इस प्रकार विगत तीन दशकों में भले ही उत्पदन बढ़ा हो, भले ही कुछ वर्गो की आय बढ़ी हो, भले ही ''भू–दृश्यावलर'' में परिवर्तन दिखलाई पड़ रहा हो, परन्तु आम व्यक्ति, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो या नगरीय क्षेत्र में की आर्थिक स्थिति में सुधार नही हुआ है। निर्धनता ने उसकी उत्पादन क्षमता को कम कर दिया है। अतः कृषि ही अकेले क्षेत्र में निवास करने वाली 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या का भार उठाने में असमर्थ है, तब तो और भी असम्भव हो जाता है, जबकि जनसंख्या विकास दर 25–30 प्रति दशक है। अतः क्षेत्रीय स्तर पर विकास की प्रक्रिया को तेज करने समाज का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए कृषि के अलावा अन्य उत्पादन क्षेत्रों का विकास आवश्यक है। जिन में उद्योगों का स्थान प्रमुख है। अतः क्षेत्रीय विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाने हेतु ''औधोगीकरण–प्रक्रिया को गति प्रदान करना आवश्यक है।

क्षेत्रीय स्तर पर अपनायी जाने वाली ''औधोगीकरण–प्रक्रिया'' ये जहां एक ओर अर्थव्यवस्था में सरंचनात्मक परिवर्तन तथा एकीकरण की प्रवृत्ति को तो बढ़ावा मिलेगा। ही दूसरी और श्रम की उत्पादकता और संचय–निधि में वृद्धि होगी। आर्थिक विकास की दशा मं तेजी आयेगी तथा पूंजी के पुनरूत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रकार आर्थिक उन्नति के लिए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।

मुरादाबाद मण्डल भारत के अन्य क्षेत्रों के समान आर्थिक दृष्टिकोण से पिछडा है, यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्थिति में सुधार दृष्टिकोण से पिछड़ा है, यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् स्थिति में सुधार हुआ है, परन्तु अभी इसको विकसित नही माना जा सकता है। यद्यपि किसी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के बारे में कोई राय बनाने का मुख्य पैमाना कृषि एवं उद्योग ही होते है, दोनों ही दृष्टिकोण से मुरादाबाद मण्डल की उपलब्धियाँ उत्साहजनक रही है, यह बात अलग है अब तक की

कृषि एवं औद्योगिक प्रगति क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है न ही वर्तमान उत्पादन स्तर पर मुरादाबाद मण्डल से उत्पादित वस्तुओं का भारी पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है। वर्तमान अर्थव्यवस्था की दो सबसे जटिल समस्याऐं ''बेकारी'' व ''गरीबी'' की है, ये समस्यायें कुछ अन्य समस्याओं का परिणाम है। यह समस्यायें मुरादाबाद मण्डल की अर्थव्यवस्था में कई प्रकार से प्रतिबिम्बित होती है। इन समस्याओं का समाधान करके ही क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है। आर्थिक विकास रूपी गाडी में कृषि व उद्योग दो पहिये का कार्य करते है। अतः कृषि के साथ–साथ उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

आर्थिक पिछडेपन को दूर करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने पूंजीनिवेश को बढ़ाने तथा सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने हेतु मुरादाबाद मण्डल में औधोगिकरण की प्रक्रिया को तेज करना आवश्यक है। क्षेत्रीय–स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों (जलवायु, भूमि, मिट्टी, वनस्पति, जनसंख्या आदि जिनका पूर्व के अध्यायों में वर्णन किया जा चुका है।) की स्थिति औधोगिक विकास के अनुकूल है। क्षेत्रीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनो पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों की इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है, उदनके लिए आवश्यक कच्चा माल, श्रम तथा बाजार स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध है। अतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सकता है। मुरादाबाद मण्डल के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के दूरगामी परिणाम होगें। सर्वप्रथम अतिरिक्त श्रम को काम मिल जाने से उनको आर्थिक लाभ होगा, उनकी क्रय–क्षमता में वृद्धि होगी। बाजार में वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ने से कृषि व औद्योगिक –उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। फलतः अधिक उत्पादन पर कृषक, कृषि–श्रमिक, औद्योगिक श्रमिकों को अधिक वेतन प्राप्त होने लगेगा और वही प्रक्रिया बार–बार दोहरायी जाती रहेगी। कृषक वर्ग के साथ–साथ व्यापारिक वर्ग को और अधिक व्यापारिक क्षेत्र की प्राप्ति के कारण लाभ की दशाओं में सुधार होगा। नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से ''कृषि क्षेत्र'' को दो प्रकार से लाभ होगा–प्रथम तो नवीन औद्योगिक इकाइयों में बढ़ती कच्चे माल की मांग के कारण कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कृषि क्षेत्र में बेरोजगार श्रमिकों को और अधिक रोजगार प्राप्त होगा, कृषक वर्ग की आय बढ़ जाने के कारण वे उन्नत समस्याओं का आंकलन क्षेत्रीय स्तर पर उद्यमियों, श्रमिकों व्यापारियों, औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित अधिकारियों आदि से लिये गये साक्षात्मकारों पर आधारित है।

औद्योगिक विकास के मार्ग को अवरूद्ध करने वाली कुछ प्रमुख समस्याओं का संक्षिप्त विश्लेषण इस प्रकार हैः–

1. कच्चे माल की आपूर्ति सम्बन्धी समस्यायें :–

स्थानीय कच्चे माल (गन्ना, गेहूँ,चावल, आलू, तिहलन, मैन्था, दड्डी, बांस, भाँभर घास, लकड़ी व रेत आदि) की उपलब्धता में तो किसी प्रकार की न्यूवता नहीं है। परन्तु उनकी उपलब्धता स्थिर व नियमित नही है। मौसम की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता पर उपर्युक्त कच्चे माल की आपूर्ति में उतार–चढ़ाव आता रहता है। उदाहरण के लिए 1966–67, 1971–72 व 1976–77 तथा 1980–81 के वर्षों में सूखे की स्थिति के कारण औद्योगिक फसलों का उत्पादन घट गया। उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति घट गई थी। चीनी एवं खाण्डसारी उद्योग, गन्ना–उत्पादन में आयी कमी के कारण संकट में पड गया। चीनी मिलों को बहुत ऊँचे मूल्य पर गन्ना क्रय करना पड़ा। लघु खाण्डसार इकाइयाँ के न चल पाने के परिणाम स्वरूप, क्षेत्रीय स्तर पर गन्ने की अधिकता हो गयी। मांग की कमी से गन्ना मूल्यों में गिरावट, राज्य सरकार के आदेश पर चीनी मिलों को लम्बे समय तक चलाये जाने से, मशीनों की टूट–पूट, गन्ने से चीनी प्राप्तांश की कमी आदि चल पायी। अतः मौसम की अनिश्चितता के कारण कच्चे माल की आपूर्ति में अनियमितता का स्वभाव औद्योगिक विकास को भी अवरूद्ध किये रहता है। जहाँ एक ओर कच्चे माल की आपूर्ति अनिश्चित है वही दूसरी ओर कच्चे माल की किस्म भी घटिया है। तराई पट्टी को छोड़कर गन्ने से प्राप्तांश न्यूनतम है, जो कृषक एवं उद्यमी, दोनों को ही प्रभावित करता है। सूखे के मौसम में मूंगफली का उत्पादन तो कम हो ही जाता है, साथ ही उसमें तेल की मात्रा न्यूनतम रह जाने से खाद्य तेल निर्माण उद्योग के विकास को बाधा पहुंचती है। नजीबाबाद, बढ़ापुर व अफजलगढ के क्षेत्रों में तेज गति से किये गये वन कटाव, के कारण कत्था, प्लाइवुड, फर्नीचर व कागज उद्योग के लिए कच्चे माल का अभाव बढ़ता जा रहा है। मैन्था उद्योग में मैन्था के भावों में उतार–चढ़ाव के कारण किसान मैन्था फसलों के उत्पादन में रूचि नहीं लेता है क्योंकि उसे अपने कच्चे माल का पूरा भाव नहीं मिल पाता है।

पीतल, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, चूना–पत्थर, कपास, कोयला आदि का आयात बाह्य क्षेत्रों से किया जाता है, जिससे परिवहन लागत की अधिकता, आयातित माल के बड़े भाग का मार्ग में ही नष्ट हो जाना, विदेशी कच्चे माल की आपूर्ति में विलम्ब होना, लघु उद्यमियों को अपनी आवश्यकता का बड़ा भाग पूंजी की कमी के कारण एक साथ न मंगा सकता, आदि समस्याओं का सामाना करना पड़ता है।

मुरादाबाद मण्डल की अधिकांश औद्योगिक इकाइयों लघु एवं कुटीर स्तर की है, जिनके पास कच्चे माल को क्रय करने एवं उसको संग्रह रखने हेतु पूंजी का अभाव है। फलतः वर्ष भर ऊँचे मूल्यों पर बिचौलियों से कच्चा माल क्रय करना पड़ता है। चीनी एवं खाण्डसारी उद्योगों को वर्ष में 3–6 माह ही गन्ना प्राप्त हो पाता है, पूंजीपति इस उद्योग में पूंजी लगाने से कतराते हैं, क्योंकि लाभांश प्राप्ति न्यूनतम है। क्षेत्रीय परम्परागत उद्योगों में लगे। कारीगरों का नियमित रूप से कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नगीना का आबनुल उद्योग लकड़ी के अभाव में समाप्त हो चला है। सींग बहुत ऊँचे मूल्यों पर मिलता है, फर्नीचर उद्योग लकड़ी के मूल्यों के उच्चतम स्तर तक पहुंच जाने के कारण बन्द होने की स्थिति में है। साथ ही प्लास्टिक फर्नीचर से उसे कड़ी प्रतिद्वन्दता झेलनी पड़ रही है। इस प्रकार क्ष्ज्ञेत्रीय स्तर अधिकांश लघु व विशाल औधोगिक इकाइयाँ किसी न किसी रूप में कच्चे माल की आपूर्ति की समस्या से पीड़ित है। वर्तमान में विदेशों से आयोजित उन्ही सामानों के कारण भी हमारे यह उद्योग संकट में है।

2. पूंजी–निवेश सम्बन्धी समस्यायें–

औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए, भूमि की खरीद, भवन निर्माण, मशीनों को क्रय करने, कच्चे माल को खरीदने, तैयार माल को विक्रय करने, भाण्डारण क्षमता को बढ़ाने, श्रमिकों के वेतन भुगतान एवं करों की अदायगी के लिए विशाल मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, पूंजी के अभाव में औद्योगिक इकाई के उत्पादन को भारी आघात पहुंचता है। मुरादाबाद मण्डल में प्रत्येक स्तर तथा उद्योग की इकाइयाँ पूंजी के अभाव से ग्रस्त है, उनके विस्तार व नवीन इकाइयों की स्थापना का क्रम धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। क्षेत्रीय इकाइयाँ ऋणों के बोझ से दबी है। समस्त चीनी मिलों पर कृषकों का 55 करोड रूपया भुगतान के लिए शेष है। पूंजी के अभाव में प्राचीन व घिसी–पिटी मशीनों को बदला नहीं जा सका है। स्योहारा, रामपुर, बिलारी, बिजनौर, अमरोहा चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 70–80 करोड़ रूपये की शीघ्र आवश्यकता है।मुराबाबाद पीतल उद्योग पूंजी के अभाव में दिवालिया घोषित की जा चुकी है। रामपुर की कपड़ा मिल पूंजी के अभाव में बन्द कर दी गयी, जो राज्य सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। कुटीर उद्योगों के पतन में पूंजी के अभाव का मुख्य भाग है। क्षेत्र की 38 प्रतिशत इकाइयाँ पूंजी की कमी के कारण अपने देश की इन इकाइयों के प्रति स्पर्द्धा न कर पाले के कारण बन्दी की स्थिति आ गई है। अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश चीनी मिलों पूंजी की कमी से वर्ष 2001–02 में 25 नवम्बर तक भी नहीं चला पाई थी। क्षेत्रीय स्तर पर पूंजी के अभाव के निम्नलिखित कारण है–

1. अन्य विकासशील क्षेत्रों के समान यहाँ–पर –पूंजी निर्माण की दशायें सीमित है क्योंकि विगत दशक में अतिरिक्त पूंजी निर्माण की दर मात्र 6 प्रतिशत ही रही है, जबकि राष्ट्रीय आय में 4 प्रतिशत वृद्धि के लिए आर्थिक क्षेत्र में 12 प्रतिशत पूंजी निवेश आवश्यक होता है परंन्तु क्षेत्रीय स्तर पर न्यूनतम आय, क्रय–क्षमता की कमी, अतिरिक्त पूंजी निर्माण की मन्द गति औद्योगिक विकास के मार्ग को अवरूद्ध किये है।
2. क्षेत्रीय स्तर पर विशाल कम्पनियों का अभाव है, क्षेत्र की भौगोलिक दशायें स्वदेशी व विदेशी पूंजीपतियों को अपनी ओर आकर्षित करने में असमर्थ रही है। जब बाह्म क्षेत्र की पूंजी का क्षेत्र में आगमन नही होगा, औद्योगिक विकास की गति को तेज करना चुनौती पूर्ण कार्य होगा।
3. नवीन उद्यमियों को बैकों, राजकीय वित्त निगमों तथा निजी पूंजीपतियों से ऋण प्राप्ति में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में झंझटों भरी लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, भ्रष्टाचार का बाजार गर्म है। अतः उद्यमी, विशेषतः कुटीर उद्योगों में लगे कारीगर ''इस माया जाल'' में नही फँसना चाहते हैं।
4. विगत वर्षों में ब्याज दर के उच्चतम (10%-15%) हो जाने से, नवीन व लद्यु उद्यमियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनका लाभांश घट जाता है। उपरोक्त बाधाओं व कठिनाइयों के कारण मुरादाबाद मण्डल की औद्योगिक इकाइयाँ पूंजी की समस्या से प्रभावित है, नवीन इकाइयों की स्थापना का कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।

3 ऊर्जा–आपूर्ति की समस्या –

भारत के अन्य क्षेत्रों के समान मुरादाबाद मण्डल में ऊर्जा संकट चरम सीमा पर विद्यमान है। विद्युत वितरण, विद्युत कटौती, विद्युत मूल्य की अधिकता चारों ओर अपना प्रभाव छोड़ रही है। नवीन क्षेत्रों में तो विद्युत लाइनों के निर्माण की बात ही छोड़ दी जाये। वर्तमान लाइनों में ही विद्युत प्रवाह का अभाव है। 24 घन्टे में 8–10 घन्टे विद्युत कटौती क्या औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी। इससे न केवल औद्योगिक क्षेत्र वरन् कृषि कार्य भी बुरी तरह प्रभावित है। विद्युत कटौती के कारण समस्या अर्थव्यवस्था चरमरा गयी है। जिसका हल निकट भविष्य में नजर आता है। सरकारें बदली, परिस्थितियाँ बदली, मौसम बदला, परन्तु ऊर्जा संकट ज्यों का त्यों बना है।

क्षेत्रीय स्तर पर स्थापित कांच, टिकली, सूती वस्त्र, चूना आदि उद्योग ही क्षेत्र में प्रमुखता के साथ कोयले का शक्ति के रूप में प्रयोग करते है, अन्यथा चीनी एवं खाण्डसार, कत्था, कागज, पीतल विनिर्माण, यंत्र निर्माण आदि सभी उद्योगों में विद्युत का ही प्रभुत्व है। विद्युत उत्पदन के लिए ''जनरेटर'' एवं ''डीजल'' की कमी है। इसकी लागत भी अधिक आती है। ''सौर–ऊर्जा'' का व्यावहारिक–स्तर पर प्रचलन क्षेत्रीय स्तर पर न के बराबर है। अतः जल या ताप विधुत ही ऊर्जा का एक मात्र स्त्रोत है। परन्तु मुरादाबाद मण्डल के 3470 (70%) गांव ही विद्युतीकृत है। क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए विद्युत लाइनों की लम्बाई कम है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा विधुत मूल्य बहुत बढ़ा दिये गये है। विभिन्न बाधाओं के परिणाम स्वरूप विद्युत आपूर्ति विनियमित व अपर्याप्त होने से उत्पादन लागत अधिक हो जाती है।

4. बाजार सम्बन्धी समस्यायें :–

औद्योगिक उत्पादन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तु, कितनी मात्रा में, किस मूल्य पर खरीद सकता है। अर्थात् वस्तुओं के उत्पादन की मात्रा, किस्म, रूप, रंग, आकार उपभोक्ता की मांग पर निर्भर करता है, जो बाजार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। बाजार ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का एहसास कराता है तथा उनमें नवीन वस्तुओं के उपभोग को लोकप्रिय बनाते हैं। अतः औद्योगिकरण की प्रक्रिया को गति देने हेतु दो महत्वपूर्ण पहलुओं की आवश्यकता पड़ती है, प्रथम–वस्तु की किस्म तथा दूसरे संगठित व सुदृढ़ बाजार की उपलब्धता। मुरादाबाद मण्डल में अधिकांश वस्तुएं लघु स्तर पर उत्पादित होती है। जिससे उत्पादन लगात अधिक होने के कारण वस्तुओं के ऊँचे मूल्य, उत्पादन की घटती किस्म, उत्पादन की सीमित मात्रा आदि समस्याओं के कारण वह बाजार की अपनी और आकर्षित

करने में सफल नहीं हो पाती है। मुरादाबाद मण्डल की कुल जसंख्या 1 करोड है, जो स्वयं में एक बहुत बड़ बाजार हो सकता है। कुल जनंसख्या का 7.76 प्रतिशत भाग व्यापार व विपणन व्यावसाय में लगा है। परन्तु बाजार की दशायें संतोषप्रद नहीं है अर्थात स्थानीय व बाह्य बाजारों से सम्बन्धित समस्यायें औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। कुछ महत्वपूर्ण समस्यायें इस प्रकार है–

1. आर्थिक दृष्टिकोण से पिछडे होने के कारण ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय कम है। इस न्यूनतम आय का भी 60–75 प्रतिशत भाग भोजन व वस्त्रों पर व्यय हो जाता है। फलतः आम लोगों की क्रय क्षमता कम है, जो कि उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।
2. मुरादाबाद मण्डल में चीनी, सूती वस्त्र, खाण्ड, कत्था, कागज, साबुन मैंथा आदि का उत्पादन क्षेत्रीय आवश्यकताओं से भी अधिक होता है, परन्तु उनकी किस्म उत्तम कोटि की नहीं है, जिससे वस्तुओं का विक्रय करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
3. विगत 10 वर्षों में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करने के पश्चात् भी मुरादाबाद के पीतल व इस्पात के बर्तन, कलात्मक वस्तुओं, सींग के सामान की किस्म में गिरावट तथा बेतहाशा मूल्य वृद्धि के कारण राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कमी आयी है।
4. मुरादाबाद मण्डल में वर्तमान समय में कृषि यंत्रों, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों, सिंचाई के उपकरणों, परिवहन के साधनों की विशेष रूप से आवश्यकता है, इनका बाजार भी विशाल है, परन्तु उत्पादन मांग से कम है, जबकि दूसरी ओर क्षेत्र में ऐसे बहुत सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिनकी मांग स्थानीय व बाह्य क्षेत्रों में कम है। अतः औद्योगिक विकास को मांग एवं पूर्ति के असंतुलित स्वभाव का सामना करना पड़ता है।
5. आज भी वस्तुओं के ''स्तर–निर्धारण'' की कमी है। वस्तुओं का आकार रंग–रूप निम्न कोटि का है। वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण नही है, उपर्युक्त समस्यायें बाजार की दशाओं को प्रभावित करती है।
6. बाजार की समस्या परम्परागत उद्योगों के सम्मुख सर्वाधिक है क्योंकि आज लोगों की रूचि में अन्तर आया है, आम व्यक्ति सस्ती, टिकाऊ व तड़क–भड़क वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहता है, जबकि परम्परागत उद्योगों में आज भी सामान्य विधियों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है। उत्पादन में श्रम की अधिकता के कारण उत्पादन लागत अधिक आती है। अतः ऊँचे मूल्यों के कारण वस्तुओं की मांग में आयी कमी में कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का विकास नही हो पा रहा है।

5. श्रम सम्बन्धी समस्यायें :–

यद्यपि मुरादाबाद मण्डल में अधिक जनसंख्या के कारण श्रमिकों की कमी नहीं है। उल्टे श्रमिकों में बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है किन्तु फिर भी औद्योगिक श्रमिकों से सम्बन्धित अनेक समस्यायें ज्यों की त्यों बनी है। श्रमिकों की संख्या बढने के साथ–साथ उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा है। अनेक विषयों को लेकर उद्यमियों व श्रमिकों के पारस्परिक सम्बन्धों में गिरावट आयी है। आज औद्योगिक श्रमिकों की कार्यक्षमता में कमी आयी है। इसके अतिरिक्त कार्य करने की दशाओं का निम्न स्तरीय होना, प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव, न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्ति, आवासीय समस्यायें, कुपोषण, आंदोलन, हड़ताल, कार्य में लापरवाही का बढता जाना तथा शिक्षा की कमी आदि अनेक श्रमिक समस्यायें औद्योगिक विकास को प्रभावि कर रही है। शोधकर्त्ता द्वारा श्रमिकों से की गयी बात–चीत से यह तथ्य उभर कर आया कि अधिकांश श्रमिक अपनी कार्य दशाओं व पारिश्रमिक प्राप्ति से अप्रसन्न है। लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिक 12–14 घन्टे कार्य करके 30–40 रूपये प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। काले व मैले वस्त्र, स्याही में पुते मुंह–हाथ पैश्र, पतले–दुबले शरीर, आँखों में सुनापन, उनके शोषण, अशिक्षा व आर्थिक पिछड़ेपन की कहानी को दोहराते है। पीतल, खाण्डसारी जूता निर्माण, कुटीर उद्योगों में लगे श्रमिकों को देखकर लेखमात्र भी नही लगता कि ये वही श्रमिक है, जो आंदोलन, हडताल आदि के विशेषणों से विभूषित है।

6. सहकारी स्तर पर उत्पन्न समस्यायें :–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकारी स्तर पर उद्योगों को विकसित करने हेतु अनेक प्रयास किये गये है, परन्तु सरकारी नियत्रंण, नीतियों एवं सरकारी मशनीरी के कारण क्षेत्रीय उद्योगों के सम्मुख अनेक समस्यायें उत्पन्न हो गयी है, यथा–सरकार द्वारा लागू उत्पादन कर, बिक्री कर, क्रय–विक्रय कर, मशीनों की खरीद पर एक पंजीकरण शुल्क आदि के कारण वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ जाते हैं। करों को लगाने एवं उनको वसूलने में सरकारी कर्मचारियों को खुली छूट प्राप्त होने से अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है। सरकार की नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन समयानुकूल नहीं होता है, उद्योगों का विस्तार, नवीन उद्योगों की स्थापना कच्चा माल व मशीनों के आयात तथा तैयार माल के निर्यात आदि की अनुमित अनुकूल समय के पश्चात् मिल पाती है। सरकार की दोषपूर्ण नीतियों को चीनी एवं खाण्डसारी उद्योगों में अस्थिरता बनी रहती है। सरकार की नियोजन प्रणाली भी दोषपूर्ण है, क्योंकि जो क्षेत्र, उद्योग विशेष के लिा भौगोलिक दृष्टिकोण से उपयुक्त है, वहॅा उद्योगों को स्थापित न कर, राजनैतिक दबाव के कारण ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करती है, जहाँ उनके लिए उपयुक्त भौगोलिक दशायें, उपलब्ध नहीं है, यह कदम उद्योगों के लिए आत्मघाती है। सरकारी स्तर पर श्रमिकों के हित में यद्यपि कागजी योजनायें बनाई जाती है परन्तु इनका क्रियान्वयन हो पाना मिल मालिकों के हाथ में है जो कि केवल किसी न किसी प्रकार से श्रमिकों का शोषण करते रहते हैं।

7. जलवायु सम्बन्धी समस्यायें –

यद्यपि मुरादाबाद मण्डल की जलवायु मानव, कृषि व उद्योग आदि के लिए अनुकूल है, परन्तु वर्षा की अनिश्चितता व अनिश्चितता के कारण कृषि उत्पादन में उतार–चढ़ाव आता है फलतः उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। मुरादाबाद मण्डल में मई से सितम्बर का मौसम, अधिक गर्मी, तेज हवाओं ''लू'' व वर्षा की अधिकता के कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। श्रमिकों की कार्यक्षमता घट जाती है। कच्चे व तैयार माल को रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्षा की अधिकता व बाढ़ के कारण परिवहन–व्यवस्था अपंग हो जाती है। वर्षा की अधिकता व बाढ़ के कारण परिवहन–व्यवस्था पंग हो जाती है। जो उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक फैलाव की कमी :–

मुरादाबाद मण्डल के ग्रामीण क्षेत्र निर्धानता, बेरोजगारी, कुपोषण तथा अन्य समस्याओं से ग्रस्त है, कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव को कम करना आवश्यक है, जिसक एकमात्र उपाय उद्योग धन्धों को विकसित करना है, परन्तु विभिन्न प्रयासों के बावजूद ग्रामीण जनसंख्या का मात्र 5.87 प्रतिशत भाग ही घरेलू व अन्य उद्योगों में कार्यरत है। औद्योगिक विकास की गति मन्द है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र अनेक समस्याओं से पीड़ित है– यथा–पूंजी की न्यूनता, परिवहन के साधनों की कमी, जोखिम उठाने की सीमितता, प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव परम्परागत उद्योगों का पतन, विद्युत आपूर्ति की समस्या आदि। उपर्युक्त समस्याओं के कारण उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाना पसन्द नही करता है।

9. परिवहन की समस्यायें –

यद्यपि मुरादाबाद मण्डल में पक्की सड़कों की लम्बाई 7643 किलोमीटर है तथा विगम 70 वर्गो में पक्की सड़को की लम्बाई 1000 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ी है, समस्त कस्बे व नगर पक्की सड़को से जोड़ दिया गये है, परन्तु फिर भी तराई पट्टी व गंगा खादर तथा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में, जो कि कच्चे माल तथा अन्य संसाधनों के प्रमुख स्त्रोत है, उचित व पर्याप्त मात्रा में परिवहन के साधनों की कमी है, फलतः इन क्षेत्रों में औधोगिक विकास की गति मन्द है।

10. उद्योगों की बढ़ती रूग्णता :–

पिछले दो दशकों से रूग्णता हमारे उद्योगों में जिस तेजी के साथ और निरन्तर बढ़ रही है, यह बड़ी चिन्ता का विषय है। इस रूग्णता से उत्पादन आय व रोजगार सभी बुरी तरह प्रभावित है। क्षेत्र की 90 प्रतिशत खाण्डसारी इकाइयाँ रूग्णता का शिकार है। प्रायः सभी विशाल औद्योगिक प्रतिष्ठान इससे पीड़ित है। जिसके कारण अधिकांश विशाल प्रतिष्ठानों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है परन्तु स्थिति पूर्व जैसी ही है। रूग्ण व्यक्ति की तरह, रूग्ण उद्योगों का सही निदान आवश्यक है। गलत निदान से बीमारी बढ़ती जाती है। कुछ लोगों की धारणा है कि वित्त का अभाव इसका कारण है, परन्तु उद्योग विशेष में रूग्णता बाहरी तत्वों का आन्तरिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती है अर्थात उत्पादन शुल्क, आयात व निर्यात के असामान्य नियम, लम्बे समय तक बाजार की स्थिरता, मांग व पूर्ति के मध्य असंतुलन, उत्पादन का बढ़ता खर्च, कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, कच्चे माल के मूल्यों में वृद्धि, कच्चे माल व विद्युज आपूर्ति का अभाव, वित्तीय प्रबन्ध, मशीनों की बडी टूट–फूट, क्षमता से कम उत्पादन, पुरातन, उत्पादन तकनीकी आदि कारक उद्योगों में रूग्णता को जन्म देते है और उद्योगों में बढ़ती रूग्णता औद्योगिक विकास के मार्ग को अवरूद्ध करते हैं। वर्तमान में क्षेत्र की चीनी एव खाण्डसारी मिले बन्दी के कगार पर है। बाजार में चीनी के मूल्य यथावत् है परन्तु सरकार बढ़तर मंहगाई, प्रति एकड़ बढ़ते उत्पादन मूल्य तथा किसानों के आन्दोलन के ककारण प्रतिवर्ष गन्ना मूल्य बढ़ाकर निर्धारित कर रही है। इस मूल्य पर चीनी एवं खाण्डसारी इकाइयाँ घाटे में जा रही है। इस मूल्य पर चीनी एवं खाण्डसार इकाइयाँ घाटे में जा रही है। अतः वह आज नवम्बर 2002 तक चलने की स्थिति में नही है। अतः पश्चिमी उतर प्रदेश के इस गन्ना उत्पादक क्षेत्र में जगह–जगह आन्दोलन जारी है।